**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: The Minister of Defence made a statement regarding present situation in Eastern Ladakh.

**रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) :** महोदय, मैं भारत और चीन सीमा पर हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसकी जानकारी देने के लिए, उस पर वक्तव्य देने के लिए सदन के समक्ष खड़ा हुआ हूं ।

अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष सितम्बर में इस गरीमामय सदन के समक्ष मैंने एक विस्तृत वक्तव्य ईस्टर्न लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर हुई डेवलपमेंट्स के बारे में दिया था । मैंने यह बताया था कि चीन द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल, मई 2020 के दौरान ईस्टर्न लद्दाख की सीमा के समीप भारी संख्या में सशस्त्र बल तथा गोला-बारूद आदि इकट्ठा कर लिया गया है । चीन द्वारा एलएसी के आस-पास कई बार ट्रांसग्रेशन का प्रयास भी किया गया था । हमारी सशस्त्र सेनाओं ने उन सभी प्रयासों के दृष्टिगत उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की थी ।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के साथ इस सदन ने भी उन वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी, जिन्होंने भारत की सीमा की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था । आज मैं इस सदन को कुछ और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं । पिछले वर्ष सितम्बर से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है । हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसइन्गेजमेंट तथा यथा-स्थिति, यानी स्टेटस-क्वो हो जाए, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुन: स्थापित हो सके । मैं संक्षेप में वहां की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सदन को दोबारा अवगत कराना चाहता हूं । सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर

करीब 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर पर वर्ष 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा जमा रखा है । इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा सिनो-पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट, वर्ष 1963 के तहत चीन को दे दिया है । इस प्रकार भारत की भूमि पर चीन का लगभग 43 हजार स्क्वायर किलोमीटर अनधिकृत कब्जा है । चीन पूर्वी क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर की भूमि को अपना बताता है । भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइ-लेट्रल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं । इसके साथ-साथ सीमा-विवाद के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है, लेकिन एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइ-लेट्रल टाइज पर बुरा असर पड़ता है । इससे चीन भी अच्छी तरह से अवगत है । कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में भी यह जिक्र किया गया है । एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइ-लेट्रल रिलेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है । इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है । उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बात-चीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितम्बर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा एनएसए श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बात-चीत भी शामिल है । हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसइन्गेजमेंट किया जाए, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुन: स्थापित हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं । चीन ने बड़ी संख्या में सेना और गोला-बारूद भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है । हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडीक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं । मुझे यह बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य एवं बहादुरी का परिचय पैंगोंग सो के साउथ व नॉर्थ बैंक पर दिया है । सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं । भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है । हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत रूप से अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मिलिट्री एंड डिप्लोमैटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है । इस बात-चीत में हमने चीन को यह बताया है कि तीन सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं । फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए । सेकेंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनीलैटरली स्टैटस क्वो को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए । थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए । ये तीन बातें उनके समक्ष रखी गई थीं । फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फारवर्ड डिप्लॉयमेंट, जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी-अपनी स्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं ।

अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रैटिजी तथा एप्रोच माननीय प्रधान मंत्री जी के इस दिशा-निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे । हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि

हम समझौते की स्थिति पर पहुँच गए हैं । इन दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत सितम्बर, 2020 से लगातार सैन्य और कूटनीतिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसइंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए । यह बातचीत हुई है । अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है । राजनयिक स्तर पर भी WMCC (*Working Mechanism for Consultation* and *Coordination* on India-China Border Affairs) के तहत बैठकें होती रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी इस एप्रोच तथा सस्टैंड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसइंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसइंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो, ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसइंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फारवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज़्ड, कोआर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटायेंगे । चीन अपनी टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा । मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ । चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा ।…(व्यवधान)

**श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद):** क्या आप फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर पाएंगे?…(व्यवधान)

**श्री राज नाथ सिंह :** आप रूक जाइए, मैं बताता हूँ ।…(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए ।

...(व्यवधान)

**श्री राज नाथ सिंह :** हम बताएंगे । वह भी बताते हैं ।...(व्यवधान) नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर थ्री के पास अपने परमानेन्ट बेस धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा । इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी । ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्माण आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल, 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है, उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी ।

महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियाँ, जिसमें परम्परागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है को अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे । पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा । इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारम्भ हो गई है ।

महोदय, मैं सदन को इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरी अभी तक की जो जानकारी है यानी स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं इस सदन में आ रहा था, तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है, उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है । अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ अपने परमानेन्ट बेस पर वापस जा चुकी हैं । यह हमें जानकारी मिली है ।

महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है ।...(व्यवधान) मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहूँगा ।...(व्यवधान) मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहता ।...(व्यवधान) आप चिंता मत करिए, हमें ज्यादा चिंता है ।...(व्यवधान)

महोदय, मैं इस सदन को पुन: आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं है ।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पैट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ बचे हैं । इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा । दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि बायलेट्रल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसइंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए । यह सहमति बनी है । अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की सम्प्रभुता की रक्षा के हमारे इस संकल्प से अवगत है । हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिल कर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गम्भीरता से प्रयास किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ सम्पूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरि-भूरि प्रशंसा करे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसइंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की सम्प्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

[Placed in Library, See No. LT 3208/17/21]